भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 587
जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है।
1 श्रावण, 1947 (शक)

मुफ़्त और ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर

587. श्री अरुण भारतीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मालिकाना सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में एकाधिकार पर अंकुश लगाने के लिए मुफ़्त और ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर (एफओएसएस) को अपनाने को बढ़ावा देने हेतु कोई नई नीतियाँ शुरू की हैं;
(ख) उन प्रमुख सरकारी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्होंने एफओएसएस समाधानों को अपनाया है और सार्वजनिक सेवा वितरण और लागत बचत पर उनका प्रभाव संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) छात्रों में डिजिटल साक्षरता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में एफओएसएस उपकरणों को एकीकृत करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) देश में एफओएसएस विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई पहलों में वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और डेवलपर्स तथा स्टार्टअप्स के लिए कौन से प्रोत्साहन शामिल हैं; और
(ङ) लोक प्रशासन और निजी क्षेत्रों में एफओएसएस को व्यापक रूप से अपनाया जाना सुनिश्चित करने में क्या चुनौतियाँ हैं और उनके समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ) : भारत सरकार की डिजिटल रणनीति प्रधानमंत्री जी के प्रौद्योगिकी लोकतंत्रीकरण के दृष्टिकोण पर आधारित है। सरकार ने आधार, डिजिलॉकर, पीएम गति शक्ति, आरोग्य सेतु, एकीकृत भुगतान इंटरफेस आदि जैसे कई डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। विशिष्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम/समाधानों के उपयोग हेतु नीतियाँ समय-समय पर तय की जाती हैं और ये तकनीकी एवं सुरक्षा आवश्यकताओं पर आधारित होती हैं।

*****